इकाई 7 गांव, कस्बा और नगर

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 गांव और इसकी विशेषताएं

- 7.2.1 ग्राम स्वायत्तता का मुद्दा
- 7.2.2 गांव और उसकी सामाजिक संरचना
- 7.2.3 जजमानी व्यवस्था
- 7.2.4 ग्राम शक्ति संरचना और नेतृत्व में परिवर्तन

7.3 ग्राम एवं वृहद राजनितिक व्यवस्था

- 7.3.1 पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव
- 7.3.2 ब्रिटिश भारत में गाँव
- 7.3.3 समकालीन भारत में गाँव

7.4 भारत में कस्बे और नगरः नगरीकरण के स्वरूप

- 7.4.1 एक नगर या नगर की परिभाषा
- 7.4.2 जनसांख्यिकी पहलू
- 7.4.3 स्थानिक स्वरूप

7.5 कस्बों और नगरों का विकास

- 7.5.1 प्रवास
- 7.5.2 सामाजिक-सांस्कृतिक चरित्र

7.6 नगरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया के संबंध में समस्याएं

7.7 सारांश

7.8 संदर्भ

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई से गुजरने के बाद, आप निम्न कार्य कर पाएंगेः

- भारत में गाँव की विशेषताओं का वर्णन;
- गाँव की सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं;
- नगरीकरण और नगरी क्षेत्रों की प्रक्रिया को परिभाषित करना;
- कस्बों की विशेषता पर चर्चा;
- नगरों की विशेषताओं को रेखांकित करना और अंत में;
- कस्बों और नगरों की सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताना।

7.1 प्रस्तावना

आपने भारत में जनजातियों की विशिष्ट विशेषता के बारे में सीखा था। हमने भारत में आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बदलती आजीविका का वर्णन किया। यहां, इस इकाई, इकाई-07 गांव, कस्बा और नगर में, हम गाँव के विभिन्न पहलुओं यानि ग्रामीण समाज और कस्बों और नगरों की व्याख्या करेंगे जो भारतीय समाज के नगरी सामाजिक ढांचे का हिस्सा हैं।

गाँव, कस्बा और नगर मानव बस्तियों की श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। बहुत बार गाँव के लोग नई आजीविका और व्यवसायों की तलाश में नगरों और नगरों की ओर पलायन करते हैं। ग्रामीण अपने कृषि उत्पादों को पास के कस्बों और नगरों में बेचते हैं और आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं, जिन्हें वे खुद नहीं उगा सकते हैं और न ही पैदा कर सकते हैं। वे कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए कस्बों और नगरों पर निर्भर हैं। नगरवासी सब्जियों, खाद्यान्नों, दूध, मानव श्रम आदि जैसे खाद्य उत्पादों के लिए गाँवों पर निर्भर हैं। यहाँ उल्लेख करने वाली बात यह है कि मानव बंदोबस्त की श्रेणियां गांव और नगर पर कच्चे माल के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं और नगर अन्य सुसज्जित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें उच्च प्रौद्योगिकी और अधिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए, वे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं लेकिन कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। इस इकाई में हम मानव बस्तियों की इन तीन श्रेणियों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगेरू गाँव, नगर और कस्बा। इससे छात्रों को इन श्रेणियों की स्पष्ट समझ हो सकेगी।

7.2 गांव और उसकी विशेषताएं

भारत एक ऐसा देश है जहाँ अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 640,887 गांव हैं। इनमें से ज्यादातर गांवों में 1000 से कम निवासी हैं। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हाल के समय में भी, 31 प्रतिशत नगरी निवासियों की तुलना में 69 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हैं। इसलिए, हम कह सकते हैं कि भारत गांवों का देश है। जैसा कि गाँव ग्रामीण समाज की मूल इकाई है और भारतीय आबादी का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, भारतीय समाज की बेहतर समझ रखने के लिए आपको भारतीय गाँवों की मूल विशेषताओं, उनके विकास, उनकी प्रकृति और संरचना, संस्कृति और ग्रामीण जीवन पद्धति की व्याख्या करना अनिवार्य है।

7.2.1 ग्राम स्वायत्तता का मुद्दा

भारत में औपनिवेशिक शासन के शुरुआती दौर में हेनरी मेन (1881), चार्ल्स मेटकाफ (1833) और बाडेन-पॉवेल (1896) के अध्ययनों ने ग्राम स्वायत्तता की एक अतिरंजित धारणा दी। भारतीय गांव को 'बंद' और 'पृथक' प्रणाली के रूप में चित्रित किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की प्रवर समिति की एक रिपोर्ट में, भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक चार्ल्स मेटकाफ (1833) ने भारतीय गांव को एक अखंड, एकाकी और अपरिवर्तनीय इकाई के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा, 'गाँव के समुदाय थोड़े गणतंत्रीय हैं, उनके पास लगभग हर चीज जो वे अपने भीतर चाहते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र हैं'। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि युद्ध इस पर गुजरते हैं, शासन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक समाज के रूप में गाँव हमेशा स्थिर, अपरिवर्तित और आत्मनिर्भर 'रहा है।

हाल के ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय गाँव शायद ही कभी गणतंत्र था। यह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं था। इसका व्यापक समाज के साथ संबंध है, गाँव की पलायन, कार्य और व्यापार के लिए आंदोलन, प्रशासनिक संबंध, अंतर्राज्यीय बाजार, अंतर-ग्रामीय आर्थिक और जाति संबंध और धार्मिक यात्रा अतीत में प्रचलित थे, जो गाँव को पड़ोसी गाँवों और व्यापक से जोड़ते समाज थे । इसके अलावा, आधुनिक काल में आधुनिकीकरण की नई ताकतों ने अंतर-गाँव और ग्रामीण-नगरी सहभागिता को बढ़ाया है।

लेकिन बाहरी संपर्क बढ़ने के बावजूद गाँव अभी भी एक बुनियादी सामाजिक इकाई हैं (मैंडेलबाउम 1972, ओरेनस्टीन 1965)। एक गाँव में रहने वाले लोगों में आम पहचान की भावना होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिक्षेत्र में पारिवारिक, जाति और वर्ग के स्तर पर उनके पास अंतरा -ग्रामीण संबंध हैं। वास्तव में, ग्राम जीवन पारस्परिकता, सहयोग, प्रभुत्व और प्रतिस्पर्धा की विशेषता है।

भारत प्राचीन सभ्यता का एक देश है जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखा जाता है, जो तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. तब से जब ऋग-वैदिक काल (लगभग 1500-1000 ई.पू.) के दौरान एक छोटे से अंतराल को छोड़कर जब नगरी केंद्रों को खत्म कर दिया गया था, भारत में ग्रामीण और नगरी केंद्रों का सह-अस्तित्व था। ग्रामीण और नगरी केंद्र जीवन के कुछ सामान्य पहलुओं को साझा करते हैं। वे विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, नगरी प्रवास, और कस्बों या नगरवासियों या विभिन्न उत्पादों (जैसे खाद्यान्न, दूध, सब्जियां, उद्योग के लिए कच्चे माल) के लिए गांवों पर निर्भरता और विनिर्मित वस्तुओं और बाजार के लिए कस्बों के ग्रामीणों की बढ़ती निर्भरता पर निर्भर करते हैं। । दोनों के बीच इस अंतर-निर्भरता के बावजूद कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें उनके आकार, जनसांख्यिकीय संरचना, सांस्कृतिक जीवन, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में एक-दूसरे से अलग करती हैं। (इग्नू: 191 19: ईएसओ -12 इकाई: 2 ग्रामीण सामाजिक संरचना, पृष्ठ 35)

7.2.2 गाँव और इसकी सामाजिक संरचना

परिवार लगभग सभी समाजों की मूल इकाई है। यह भारत में विशेष रूप से सच है जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी और उसके परिवार की स्थिति और सामाजिक स्थिति पर निर्भर है।

ग्रामीण भारत में परिवार

परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो ग्रामीण समाज का गठन करती है। यह जरूरतों को पूरा करता है और कार्य करता है, जो सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता, एकीकरण और परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि, प्रजनन, उत्पादन और समाजीकरण।

मोटे तौर पर दो प्रकार के परिवार हैं : (i) एकाकी परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं, और (ii) संयुक्त या विस्तारित परिवार में एकाकी प्रकार की तुलना में कुछ अधिक परिजन शामिल हैं। परिवार संयुक्तता 'के महत्वपूर्ण आयाम हैं साथ -साथ रहना, संयुक्त सम्पत्ति, सहभोजन, पीढ़ीगत जुड़ाव (तीन पीढ़ी तक), और परिजनों और भावुक पहलू के प्रति दायित्व की पूर्ति। साथ-साथ रहना का मतलब है कि एक परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। सहभोजन का तात्पर्य है कि वे एक साथ भोजन करते हैं यानी, एक सामान्य रसोईघर है। संयुक्त सम्पत्ति का मतलब है कि उनके पास संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है। इसके अलावा, पीढ़ी की गहराई में तीन पीढ़ियों या अधि

ाक, यानी दादा, पिता और पुत्र या अधिक शामिल हैं। परिवार के सदस्यों के भी अपने परिजनों के प्रति दायित्व होते हैं। इसके अलावा, उन्हें संयुक्त परिवार के आदर्श के लिए एक भावुक लगाव है।

ग्रामीण परिवार आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की इकाई के रूप में काम करता है। सामाजिक जीवन में परिवार की सामूहिकता पर जोर दिया जाता है, और व्यक्तिगत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावनाएं बहुत सीमित हैं। विवाह को एक अंतर-व्यक्तिगत मामले के बजाय एक अंतर-पारिवारिक मामला माना जाता है। यह रिश्तेदारी के नियमों द्वारा शासित है।

इसे ग्राम बहिर्मुखी और उत्तर में 'गोत्र बहिर्मुखी' के नियमों के प्रसार में देखा जाता है, लेकिन दक्षिण में नहीं। उत्तर में, किसी को अपने गाँव में विवाह करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह के जाति के अन्य गांवों के लोगों के साथ विवाह गठबंधन संपन्न होता है। लेकिन दक्षिण में ऐसा कोई भी प्रतिबंध मौजूद नहीं है। इसके अलावा, उत्तर में वह अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। इसके विपरीत, क्रॉस कजिन मैरिज यानी भाई और बहन के बच्चों के बीच शादी, दक्षिण में पसंद की जाती है। इस प्रकार, उत्तर भारत में एक केन्द्रापसारिक प्रवृत्ति है, अर्थात, शादी की दिशा समूह से बाहर या दूर है। दक्षिण भारत में इसके विपरीत हम विवाह गठजोड़ बनाने और रिश्तेदारी संबंध बनाने में एक केंद्रित प्रवृत्ति पाते हैं। दूसरे शब्दों में, विवाह समूह के भीतर या भीतर होते हैं। (इग्नू: 201 2017: पृष्ठ 26 -2) गाँव की सामाजिक संरचना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जजमानी प्रणाली थी।

आपने इस खंड में इकाई 5 जाति में गाँव की इस संस्था के बारे में समझ लिया है । अगले भाग में हम इस सामाजिक संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं।

7.2.3 जजमानी व्यवस्था

भारत में पारंपरिक गाँव के जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पारम्परिक 'जजमानी प्रणाली' है। इसका अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों, अर्थात, विलियन वाइजर (1936), एस. सी. दूबे (1955), ओप्लर और सिंह (1986), के. ईश्वरन (1967), लुईस और बार्नव्यू (1956) ने किया है। ''जाजमन'' शब्द विशेष सेवाओं के संरक्षक या प्राप्तकर्ता को संदर्भित करता है और ''जजमानी'' शब्द पूरे संबंध को संदर्भित करता है। वास्तव में, जजमानी प्रणाली एक गांव में विभिन्न जाति समूहों के बीच आर्थिक, सामाजिक और अनुष्ठान संबंधों की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत कुछ जातियां संरक्षक हैं और अन्य जातियां हैं। सेवारत जातियाँ जमींदार ऊपरी और मध्यवर्ती जाति को अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं और बदले में उन्हें नकद और तरह दोनों तरह से भुगतान किया जाता है। संरक्षक जातियाँ भूमि पर हावी होने वाली जातियाँ हैं, जैसे, उत्तर में राजपूत, भूमिहार, जाट और आंध्र प्रदेश में कम्मा, लिंगायत और रेड्डी और गुजरात में पटेल। सेवा जातियों में ब्राह्मण (पुजारी), नाई, बढ़ई, लोहार, जल-वाहक, चमड़े के काम करने वाले आदि शामिल हैं।

जजमानी संबंध अनिवार्य रूप से पारिवारिक स्तर पर संचालित होते हैं (मंडेलबाम 1972)। राजपूत भूमि के मालिक परिवार में ब्राह्मण, नाई, बढ़ई आदि के एक-एक परिवार के साथ अपने जजमानी संबंध होते हैं, और सेवा जाति का एक परिवार जाजमनों के विशिष्ट परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि, जजमानी नियम जाति पंचायतों द्वारा लागू किए जाते हैं।

जजमानी संबंध माना जाता है और अक्सर टिकाऊ, अनन्य और एकाधिक होता है। जजमानी संबन्ध को दोनों ओर अर्थात् संरक्षक और ग्राहक (जजमान और कामिन) विरासत

में मिला है। रिश्ता विशिष्ट परिवारों के बीच होता है। इसके अलावा, यह सेवा के बदले अनाज और धन के आदान-प्रदान से अधिक है। शादी, जन्म और मृत्यु जैसे विभिन्न अनुष्ठानों के अवसर पर, सेवा-जातियां अपने जजमान को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं और प्रथागत भुगतान के अलावा उपहार प्राप्त करती हैं। गुटीय प्रतियोगिताओं में प्रत्येक पक्ष अपने जजमानी सहयोगियों के समर्थन को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए जजमानी प्रणाली में गांवों में जाति और परिवारों के बीच परस्पर निर्भरता, पारस्परिकता और सहयोग शामिल है।

लेकिन जजमानी प्रणाली में प्रभुत्व, शोषण और संघर्ष (बीडेलमैन 1959 और लुईस और बार्नव्यू 1956) के तत्व भी हैं। जमींदार प्रमुख संरक्षकों और गरीब कारीगरों और उनकी सेवा करने वाले भूमिहीन मजदूरों के बीच शक्ति के व्यायाम में बहुत अंतर है। अमीर और शक्तिशाली जजमान अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए गरीबों के कामिन (ग्राहक) का शोषण करते हैं और उनका शोषण करते हैं। वास्तव में, जैजमनी प्रणाली में पारस्परिकता के साथ-साथ वर्चस्व भी है।

इसके अलावा, यह विशेष रूप से 1947 में आजादी के बाद देखा गया है, बाजार की ताकतों, नगरी संपर्क, प्रवास, शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के कारण सेवा जातियों की ओर से जजमानी प्रणाली वर्षों से कमजोर हुई है।

7.2.4 ग्राम शक्ति संरचना और नेतृत्व में परिवर्तन

विभिन्न कारकों के कारण जैसे भूमि सुधार, पंचायती राज, संसदीय राजनीति, विकास कार्यक्रम और कृषि आंदोलन के कारण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गांवों में शक्ति की संरचना और नेतृत्व में सीमांत परिवर्तन हुए हैं जिनकी प्रकृति सामंजस्यपूर्ण रही है । सिंह (1986) के अनुसार, उच्च जातियां अब अपने अधिकार की पारंपरिक वैधता से नहीं, बल्कि निचली जातियों के लोगों के साथ जोड़-तोड़ और सहयोग के जरिए सत्ता का इस्तेमाल करती हैं। पारंपरिक शक्ति संरचना नहीं बदली है। नए अवसर कम शक्तिशाली वर्ग को शक्ति की आकांक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन उनका आर्थिक पिछड़ापन उनकी इच्छाओं को विफल करता है। बी.एस. कोहन (1962), और सिंह आर. (1988) ने भारत के बारह गांवों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में, भूमि-स्वामित्व और समूहों के वर्चस्व के स्तर के करीब पाया। अब युवा और साक्षर लोग तेजी से नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना में बदलाव के स्वरूप में कुछ क्षेत्रीय बदलाव भी देखे गए हैं।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही उत्तर पर टिक मार्क करें।

क) भारत में ग्राम स्वायत्तता 'की अवधारणा किसने प्रचलित की?

i) लॉर्ड वेलेजली

ii) चार्ल्स मेटकाफ

iii) विलियम बेंटिक

iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

ख) निम्नलिखित में से ग्रामीण भारत के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थानों की पहचान करना।

i) परिवार

ii) जाति

iii) गांव

iv) ये सभी

ग) भारत में परिवार संयुक्तता की विशेषता है :

i) संदायादता

ii) साथ-साथ रहना

iii) सहभोजन

iv) ये सभी

घ) ग्रामीण भारत में जाति की पारंपरिक सांस्कृतिक विशेषताओं में मूल-भूत परिवर्तन हुआ है

1) वैवाहिक आयाम

2) सहभोजी आयाम

3) अनुष्ठान आयाम

4) इनमें से कोई नहीं

ii) लगभग सात लाइनों में जजमानी प्रणाली का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

7.3 गांव और वृहद राजनितिक व्यवस्था

भारतीय गांवों को उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्व-शासन के अपने सरल रूप के साथ 'छोटे गणतंत्र' के रूप में वर्णित किया गया था, और भूमि के उत्पादन में हिस्सेदारी का दावा करने और युद्धों में सेवा करने के लिए युवा पुरुषों की मांग को छोड़कर उच्च राजनीतिक प्राधिकरण का लगभग कोई हस्तक्षेप नहीं था। गाँव सामान्य रूप से कार्य करते थे, इस बात से असंबद्ध थे जिसका वे भाग थे उन राज्यों में कौन सिंहासन पर बैठा हुआ है । उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के रूप में भी वर्णित किया गया था, जो लगभग हर चीज को अपने भीतर चाहते थे। भारतीय गाँवों का यह वर्णन अति-सरलीकृत है। फिर भी इसने कार्ल मार्क्स और हेनरी मेन जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों और महात्मा गांधी जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों के विचारों को प्रभावित किया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही कुछ सामाजिक मानवविज्ञानी, जिन्होंने भारतीय गाँवों का गहन अध्ययन किया, भारतीय गाँव के पारंपरिक विवरण पर सवाल उठाने लगे। अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने प्रदर्शित किया कि भारतीय गाँव व्यापक समाज और सभ्यता का हिस्सा रहा है न

कि श्छोटे गणराज्योंश का, जैसा कि ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा वर्णित है।

7.3.1 पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव

यह कहना कि पूर्व-ब्रिटिश भारत में (अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन के सुदृढ़करण से ठीक पहले की अवधि) सिवाय स्थानीय सरदार या राजा को कर चुकाने के और उसे अपने युद्धों के लिए जवान मुहैया कराने के लिए गाँव राजनीतिक रूप से स्वायत्त था। राजा और उसकी प्रजा के बीच का एक संबंध जटिल था। राजा ने अपनी प्रजा के प्रति कई कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने सिंचाई के लिए सड़कें, टैंक और नहरों का निर्माण किया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी किया और भूमि को ब्राह्मणों को और धार्मिक कार्य के लिए उपहार में दिया। वह सभी जाति पंचायतों के प्रमुख थे और आपसी जाति श्रेणियों के बारे में विवादों का अंत उनके द्वारा किया गया था। यह समारोह हिंदू शासकों तक ही सीमित नहीं था, यहां तक कि मुगल राजाओं और सामंतों ने जाति को प्रभावित करने वाले सवालों का निपटारा किया।

पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव उनके राज्य के संबंध में निष्क्रिय नहीं थे (ज्यादातर रियासतें, जिन्हें देश भी कहा जाता है)। वे निश्चित रूप से इस बात से चिंतित थे कि सिंहासन पर कौन बैठा है। वे एक ऐसे राजा को पसंद करेंगे जो उन्हें ठग और दंगाई सैनिकों से बचाएगा। यदि राजा या प्रमुख स्थानीय रूप से प्रभावी जाति के होते हैं, तो उनकी जाति के साथी संकट में उनकी सहायता के लिए आते थे ।

शासकों के साथ उनके संबंध में गाँव असहाय नहीं थे। ग्रामीण विद्रोह कर सकते थे और सिंहासन के लिए एक प्रतिद्वंद्वी का समर्थन कर सकते थे। ग्रामीणों के लिए अपने दमन के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष एक और तरीका था। ऐसी सामूहिक संघर्ष होने पर शासक बहुत बार हारे थे। चूंकि भूमि बंदोबस्त के लिए उपलब्ध थी, जबकि श्रम दुर्लभ था एक शासक को इस दशा में जोत भूमि प्राप्त करना मुश्किल होगा और राजस्व का नुकसान होगा।

इस प्रकार गाँव और शासक के बीच का संबंध एक जटिल था और पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव को एक ष्छोटे गणराज्यष के रूप में वर्णित करना गलत है। हालाँकि इस बात पर ध यान दिया जाना चाहिए कि सड़कों की अनुपस्थिति और खराब संचार के कारण, गाँव ने स्वायत्तता के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था के उच्च स्तर से कम नियंत्रण का भी भरपूर आनंद उठाया। राजाओं ने ग्रामीणों को दिन-प्रतिदिन के मामलों में खुद को नियंत्रित करने दिया।

ग्राम पंचायत ने मुख्य रूप से प्रमुख जाति का गठन किया जो स्थानीय मामलों में अधिकार का इस्तेमाल करती थी, अंतर-जातीय विवादों को सुलझाती थी और गाँव में कानून व्यवस्था बनाए रखती थी।

7.3.2 ब्रिटिश भारत में गाँव

ब्रिटिश शासन ने गाँव और शासक के बीच के संबंध को बदल दिया। संचार के विकास के बाद राजनीतिक विजय हुई। इसने अंग्रेजों को एक प्रभावी प्रशासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। पुलिस, राजस्व अधिकारी और अन्य जैसे सरकारी कर्मचारी गाँव में आए। अंग्रेजों ने कानून अदालतों की एक प्रणाली स्थापित की। प्रमुख विवादों और आपराधिक अपराधों को अदालत में निपटाना पड़ा। इससे ग्राम पंचायत की शक्ति बहुत कम हो गई।

7.3.3 समकालीन भारत में गाँव

आजादी के बाद से, संसदीय लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार की शुरुआत ने गाँव को व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के साथ और भी अधिक एकीकृत बना दिया है। ग्रामीण न केवल ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के सदस्यों का चुनाव करते हैं, बल्कि राज्य विधानसभा और संसद के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल गांव में सक्रिय हैं और अपनी पार्टियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम जैसे सामुदायिक विकास योजनाएं गांव को प्रभावित करती हैं।

हालाँकि गाँव एक राजनीतिक पंचायत है जो दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के लिए निर्वाचित पंचायत है, यह जिला या जिला का हिस्सा है, जो राज्य का हिस्सा है। राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है। राजनीतिक प्रणाली के इन विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर अंतः - क्रिया है। (इग्नू: 1919, ईएसओ-12 पृष्ठ 51-53)

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव को लिटल रिपब्लीक लघु गणतंत्र क्यों कहा गया था? अपने उत्तर के लिए लगभग चार पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) बताएं कि गाँव एक ''लघु गणतंत्र'' है, यह एक सरलीकृत कथन था। अपने उत्तर के लिए लगभग छह पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

7.4 भारत में कस्बे एवं नगर : नगरीकरण के बदलते स्वरूप

भारत बीसवीं शताब्दी में तेजी से नगरीकरण के दौर से गुजरा। आधुनिक नगरी केंद्र विविध आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य करते हैं। यहाँ, किसी एक गतिविधि के मामले में कस्बों और नगरों को वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर, लोग कुछ प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर नगरी क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग उल्लेख करते हैं कि दिल्ली, कोलकाता,

वाराणसी, लखनऊ आदि जैसे ऐतिहासिक नगर हैं, औद्योगिक नगर जैसे गाजियाबाद, मोदीनगर, कानपुर, जमशेदपुर, भिलाई आदि, धार्मिक नगर जैसे मथुरा, हरद्वार, मदुरै, इलाहाबाद आदि प्रतिश्ठित नगर हैं। फिल्म बनाने के लिए, मुंबई और चेन्नई नगर , एक ग्रामीण या एक छोटे नगर के निवासी के लिए एक विशेष आकर्षण की तरह है। समाजशास्त्र में, हम इसके जनसांख्यिकीय, स्थानिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में नगरीकरण के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन पहलुओं को उठायें, हमें यह भी संक्षेप में समझते हैं कि हम भारतीय संदर्भ में एक नगर को कैसे परिभाषित करते हैं।

7.4.1 एक नगर या नगर की परिभाषा

भारत में, जनसांख्यिकी और आर्थिक सूचकांक विशिष्ट क्षेत्रों को नगर या नगर के रूप में परिभाषित करने में महत्वपूर्ण हैं। भारत में एक नगरी क्षेत्र के निश्चित मापदंडों ने वर्षों में कई बदलाव और संशोधन किए हैं। 1901 की जनगणना में अपनाई गई नगर की निम्नलिखित परिभाषा का 1961 तक उपयोग किया गया था।

क) प्रत्येक नगरपालिका, छावनी और सभी सिविल लाइन्स (एक नगर पालिका में शामिल नहीं), और

बी) स्थायी रूप से 5,000 से कम व्यक्तियों द्वारा बसाए गए घरों का हर दूसरा निरंतर संग्रह, जिसे जनगणना के प्रांतीय अधीक्षक एक नगर के रूप में मान सकते हैं।

किसी भी क्षेत्र या निपटान को नगरी के रूप में वर्णित करने का मुख्य मानदंड उसका प्रशासनिक ढांचा और आकार था न कि आर्थिक विशेषताएं। इस परिभाषा के परिणामस्वरूप कई कस्बों को वास्तव में केवल अधिक आबादी वाले गांवों के रूप में माना जाता था।

1961 में 'नगरी क्षेत्र' को अन्य प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय सुविधाओं के अलावा आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्परिभाषित किया गया था। 1961 की जनगणना में अपनाई गई परिभाषा का उपयोग 1971 और 1981 में भी किया गया था। और यह 1991 और 2001 में भी अपरिवर्तित रही। इस परिभाषा के अनुसार एक नगरी क्षेत्र हैः

क) एक जगह जो या तो एक नगर निगम या एक नगर निगम क्षेत्र है, या एक नगर समिति या एक अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड के तहत,

ख) कोई भी स्थान जो निम्न मानदंडों को पूरा करता हैः

- न्यूनतम 5,000 व्यक्ति
- कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष कामकाजी आबादी व्यवसायों में होनी चाहिए जो गैर-कृषि है,
- प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति से कम का घनत्व नहीं है, और
- एक जगह पर कुछ स्पष्ट नगरी विशेषताओं और सुविधाएं होनी चाहिए जैसे कि नए पाए गए औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी आवासीय बस्तियां, पर्यटन महत्व के स्थान और नागरिक सुविधाएं।

1961 और 1971 के बाद से इस परिभाषा में एक मामूली बदलाव हुआ है। 1991 और 1981 के बाद वानिकी, मछली पकड़ने, पशुधन, शिकार, प्रवेश, वृक्षारोपण और बागों आदि के व्यवसाय में श्रमिकों, जिन्हें पहले औद्योगिक गतिविधि के रूप में माना जाता था। 1981 और 1991 में कृषि गतिविधि के रूप में मान्यता प्राप्त कृषि व्यवसाय के रूप में गिना गया।

अच्छी तरह से परिभाषित कस्बों और/या नगरों के अलावा, नगरों और अधिक बढ़ी हुई आबादी को भी नगरी समूहों के रूप में माना गया है। 1961 की जनगणना में, 'टाउन ग्रुप' की अवधारणा को नगरी प्रसार से संबंधित एक व्यापक चित्र प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था। यह 1971 में नगरी निरंतरता, प्रक्रिया और नगरीकरण और अन्य संबंधित मामलों के रुझानों के संबंध में बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नगरी समुदाय की अवधारणा के साथ परिष्कृत किया गया था। बिना किसी बदलाव या संशोधन के यह अवधारणा 2001 की जनगणना तक संचालित रही।

जो एक नगरी समूह एक निरंतर नगरी प्रसार बनाता है और आम तौर पर एक कस्बे और उसके आस-पास के नगरी वृद्धि या दो या अधिक भौतिक रूप से सन्निहित नगरों के साथ-साथ सन्निहित और अच्छी तरह से संगठित वृद्धि होते हैं, (जनगणना रिपोर्ट 2001)

नगरी स्थानों का वर्णन करते हुए, भारतीय जनगणना रिकॉर्ड में नगरी क्षेत्र को छह वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए जनसंख्या के आकार को लगातार नियोजित करती है जैसा कि तालिका 7.1 में दिखाया गया है।

तालिका 7.1: नगरों का वर्गीकरण

वर्ग स के साथ	1,00,000	और अधिक		जनसंख्या
वर्ग I के साथ	50,000	से	99,999	जनसंख्या
वर्ग II के साथ	20,000	...	49,999	जनसंख्या
वर्ग III के साथ	10,000	...	19,999	जनसंख्या
वर्ग IV के साथ	5,000	...	9,000	जनसंख्या
वर्ग V के साथस	...	5,000 से कम		जनसंख्या

1,00,000 से कम आबादी वाले नगरी स्थानों को 'कस्बों' के रूप में जाना जाता है, जबकि 1,00,000 या अधिक आबादी वाले नगरी स्थानों को 'नगरों' के रूप में जाना जाता है। दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरी केंद्रों को महानगरीय नगरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महानगरीय केंद्र बड़े पैमाने पर खपत, और लोगों, सामानों, सेवाओं और सूचनाओं की आमद की बड़ी मात्रा के आधार पर स्वयं में एक वर्ग हैं (प्रकाश राव 1982: 17)। यह वर्णन करने के बाद कि भारत में नगरी क्षेत्र को कस्बों/नगरों की विभिन्न श्रेणियों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, अब हम भारत में नगरीकरण के पैटर्न के कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं।

गतिविधि 1

आप जिस गांव, कस्बे/नगर में रहते हैं, उसकी जनसांख्यिकीय आबादी की पहचान करें और यह पहचानें कि वह किस वर्ग के आकार का है और उसके बुनियादी ढांचे पर एक पृष्ठ की एक रिपोर्ट लिखता है, साथ ही साथ अन्य आवश्यक विशेषताएँ जो आप इसे सोचते हैं और जिसकी जरूरत है। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ चर्चा करें।

7.4.2 जनसांख्यिकी पहलू

भारत में, जनसंख्या एकाग्रता नगरीकरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। नगरी जनसंख्या का प्रतिशत 1901 में 10.8 प्रतिशत से 1981 में दोगुना से थोड़ा अधिक हो गया है। और यह 2001 तक लगभग तीन गुना हो गया है, जब यह 27.8 प्रतिशत दर्ज किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरी आबादी 217,177,625 है और यह कुल आबादी का 25.72 प्रतिशत है। अब तक देश की नगरी आबादी का संबंध है, 1901 में केवल 25.85 मिलियन कस्बों में रहते थे और 1991 तक यह 8 गुना बढ़कर 217.18 मिलियन हो गई। 1 मार्च 2001 को 1027 मिलियन की कुल आबादी में से, 285 मिलियन नगरी क्षेत्रों में रहते थे। नगरी क्षेत्रों में 1991-2001 के दौरान जनसंख्या का शुद्ध जोड़ 68 मिलियन के बराबर रहा, जहां दशक 1981-1991 के दौरान यह 61 मिलियन था।

स्वतंत्रता काल के बाद नगरी आबादी में काफी वृद्धि हुई है। 1901 से 1941 तक की चालीस वर्षों की अवधि के लिए नगरी आबादी में 25.85 से 44.15 मिलियन की वृद्धि अगले दशक के 62.44 मिलियन की तुलना में काफी मामूली रही है। 1941 से 1981 तक नगरी आबादी में 115.05 मिलियन की वृद्धि हुई है। ध्यान दें कि इस जनसंख्या का 64.8 प्रतिशत 1961 से 1981 के बीच दो दशकों में बढ़ा है। इसी तरह नगरी आबादी लगभग 1971 (109.11 मिलियन) में दोगुनी हो गई है। 1991 (217.18 मिलियन)।

शुरुआती दशकों (1901-21) में नगरी लोगों की कुल आबादी के अनुपात में धीमी वृद्धि (और 1911 में भी गिरावट) थी। यह ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक और आर्थिक विकास की धीमी दर के कारण है। 1941-51 के दौरान नगरी आबादी का तेजी से विकास ज्यादातर देश के विभाजन और अन्य राजनीतिक कारणों से हुआ है, जिसके कारण नगरी क्षेत्रों में शरणार्थी प्रवासन हुआ। 1981 से पहले के दशकों में नगरी आबादी में लगातार वृद्धि नियोजित आर्थिक विकास और औद्योगीकरण के कारण नहीं हुई, बल्कि असंतुलित कृषि विकास के कारण हुई। 1981-19991 के दौरान 1971-1981 के दौरान नगरी आबादी की वार्षिक वृद्धि दर 3.83 प्रतिशत से घटकर 3.09 प्रतिशत हो गई। दशक 1971-1981 के दौरान नगरीकरण के स्तर में 3.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1981-1991 दशक के दौरान वृद्धि केवल 2.38 प्रतिशत रही है। 1991-2001 के दौरान नगरीकरण में वृद्धि और घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई। परिणामस्वरूप, नगरी जनसंख्या के प्रतिशत में लाभ की वार्षिक दर भी 1981-1991 के दशक के दौरान 1.72 से घटकर 1.02 हो गई है। यह दर्शाता है कि भारत में 1981 से नगरीकरण की गति धीमी हो गई है। (IGNOU, 2017 (पुनर्मुद्रित) BDP, ESO-12, Block-1, पृष्ठ 10)

नगरीकरण की दर में धीमी वृद्धि, हालाँकि, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर तेजी से बढ़ी। उच्च आर्थिक विकास और अन्य कारकों के कारणय नगरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या 377 मिलियन या 31.1 प्रतिशत हो गई। (भगत, आर.बी. 2011)

7.4.3 स्थानिक स्वरूप

स्थानिक असमानताओं ने भारतीय नगरी परिदृश्य को चिह्नित किया है। ये असमानताएं मुख्य रूप से क्षेत्रीय असमानताओं, असंतुलित जनसंख्या एकाग्रता और कुछ समय के कारण 'नगरी क्षेत्रों' की जनगणना परिभाषा में बदलाव के कारण उभरी हैं। इस संदर्भ में हमें दो अवधारणाओं के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता है, अर्थात् अति-नगरीकरण और उप-नगरीकरण।

i) **अति नगरीकरण**

कस्बों या नगरी क्षेत्रों में आबादी को समायोजित करने की कुछ सीमाएँ हैं, स्कूली शिक्षा, अस्पताल आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए नागरिक सुविधाएं या खानपान प्रदान करना, कुछ विशिष्ट क्षमताओं से परे, बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाएं प्रदान करना नगर प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है। मुंबई और कोलकाता नगरों के दो ऐसे उदाहरण हैं जिनकी प्रबंधन करने की क्षमता से परे नगरी-जनसंख्या वृद्धि है। यह सुविधा अति नगरीकरण के रूप में संदर्भित है।

ii) **उप-नगरीकरण**

किसी नगर के अति-नगरीकरण के साथ निकटता से संबंधित एक विशेषता है जिसे उप-नगरीकरण कहा जाता है। जब नगर आबादी से अधिक भीड़ वाले हो जाते हैं, तो इसका परिणाम उप-नगरीकरण हो सकता है। दिल्ली एक विशिष्ट उदाहरण है (दूसरों के बीच) जहां इसके चारों ओर उप-नगरीकरण की प्रवृत्ति हो रही है। उप-नगरीकरण का अर्थ है निम्नलिखित विशेषताओं की विशेषता वाले नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीकरण :

क) भूमि के नगरी (गैर-कृषि) उपयोगों में तेज वृद्धि हुई है

बी) नगर के आसपास के क्षेत्रों को अपनी नगरपालिका सीमा के भीतर शामिल करना, और

ग) नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच सभी प्रकार के गहन संचार।

अब, हम भारत में नगरीकरण के पैटर्न में पाई जाने वाली स्थानिक असमानताओं में कुछ बदलावों को भी देख सकते हैं।

7.5 कस्बों और नगरों की वृद्धि

नगरी कस्बों के विकास ने भारत में एक दिशाहीन प्रगति नहीं दिखाई दी है । नगरी 'क्षेत्रों की जनगणना परिभाषा में भिन्नता के कारण नगरी केंद्रों की संख्या में गिरावट आई। 1901 में मौजूद कुल 1,914 कस्बों में से केवल 1,430 कस्बे 1961 तक बचे थे। 1901 में कस्बों की नई परिभाषा के कारण 1901 में लगभग 480 क्षेत्रों को कस्बों के रूप में माना जाने वाला नगरी क्षेत्र खो दिया। यह इस कारण से है कि कोई व्यक्ति 1961 में 3060 की तुलना में 1961 में 2700 कस्बों में कमी देख सकता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में 1951 में 227 नगर थे, जबकि 1981 में यह संख्या घटकर 201 हो गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी देखा गया। 1991 की जनगणना में 4 ,689 स्थानों की पहचान 1941 की जनगणना के अनुसार 4 ,029 के रूप में की गई थी। 1991 के 4,689 नगरों में से 2,996 के रूप में कई वैधानिक नगर थे और 1981 में क्रमशः 2,758 और 1,271 के मुकाबले 1,693 जनगणना या गैर-नगरपालिका नगर थे। अखिल भारतीय स्तर पर, 1981 की जनगणना के 4029 नगरों में से 93 अघोषित थे और 103 थे जिन्हें 1981-1991 के दौरान संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की वैधानिक अधिसूचनाओं द्वारा कस्बों को अन्य नगरों के साथ पूरी तरह से मिला दिया गया था। 1991 के नगरी सीमा में 856 नए नगर जोड़े गए थे। अवर्गीकृत नगरों की अधिकतम संख्या पंजाब (21), कर्नाटक (19) और आंध्र प्रदेश (13) राज्यों से थी और 1991 की जनगणना में जोड़े गए वैधानिक नगरों की अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश (91) से थी।

हालाँकि 2011 की जनगणना जिसने नगरी आबादी में 2001 में पूरे देश में 27.7% की वृद्धि और 2011 में 31.1% तक वृद्धि दर्ज कीय जो कि 3.3% प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

2011 की इस जनगणना के दौरान भी कई गांवों को कस्बों के रूप में मान्यता दी गई थी, वहां भारत में कस्बों की संख्या में वृद्धि हुई।

ii) राज्यों में नगरीकरण में परिवर्तन

भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नगरीकरण का स्वरूप राज्यों में नगरी प्रभुत्व की एक दिलचस्प विशेषता को दर्शाता है। भारत के कुल नगरी आबादी में पांच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का कुल मिलाकर 56 प्रतिशत (1961 में) 55 प्रतिशत (1971 में) था। इसके विपरीत छह राज्यों ओडिशा (उड़ीसा), हरियाणा, असम (मेघालय सहित), जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में 5 प्रतिशत (1961 में) भारत की कुल नगरी आबादी का 5.5 प्रतिशत (1971 में) हिस्सा है। 1991 की जनगणना में 25.72 प्रतिशत के राष्ट्रीय जनसंख्या की तुलना में कुल जनसंख्या में नगरी आबादी का अधिक अनुपात वाले कुछ राज्य महाराष्ट्र (35. 73 प्रतिशत), गुजरात (34.40 प्रतिशत), तमिलनाडु (34.20 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (27.39 प्रतिशत) थे।)। 2001 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र (42.4 प्रतिशत) और गुजरात (37.4 प्रतिशत) के बाद तमिलनाडु (43.9 प्रतिशत) सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। नगरी आबादी का अनुपात बिहार में सबसे कम 10.5 प्रतिशत है, उसके बाद असम (12.7 प्रतिशत) और ओडिशा (14.9 प्रतिशत) है। हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य है। स्पष्ट है कि कुछ राज्यों में नगरी प्रभुत्व इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में भी जारी है।

1961 और 1971 के बीच भारतीय राज्यों के लिए नगरी घनत्व का प्रकार कुछ इसी तरह का रुझान दिखाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और केरल के राज्यों में 1961 में प्रति वर्ग किलोमीटर 2948 व्यक्तियों के अखिल भारतीय औसत से अधिक घनत्व है। 1971 में भी इसी तरह की प्रवृत्ति पाई गई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान राज्यों में 1961 में अखिल भारतीय औसत 2,048 से कम घनत्व था।1971 की जनगणना में 1961 में देखी गई उसी प्रवृत्ति को दर्षाया गया था, जो उपरोक्त राज्यों के संबंध में थी। गुजरात, मध्य प्रदेश और असम के लिए नगरी घनत्व 1961-71 दशक के दौरान संभवतः लोगों के बाहरी प्रवास के कारण कम हो गया । वर्ष 1991 में, पश्चिम बंगाल राज्य में नगरी घनत्व सबसे अधिक था, इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब थे। तमिलनाडु, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान राज्यों में 1991 के अखिल भारतीय औसत 3,370 से भी कम घनत्व था। इस प्रकार जब हम जनगणना के आंकड़ों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि नगरी घनत्व के संदर्भ में वर्ष 1991 तक परिवर्तन लगभग अपरिवर्तित रहा।

iii) नगरों में जनसंख्या एकाग्रता

बड़े नगरी केंद्रों (1,00,000 या अधिक) के साथ जनसंख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। 1981 में भारत में 60 प्रतिशत से अधिक नगरी आबादी इस श्रेणी के नगरों में रहती थी। 1991 तक उनकी दर लगभग 65 प्रतिशत तक पहुंच गई। 1991 की जनगणना के अनुसार, 300 नगरों में जनसंख्या की कुल संख्या 1,00,000 से अधिक है। ये 300 नगरी समूह/नगर देश की नगरी आबादी का 64.89 प्रतिशत हैं। महाराष्ट्र और

पश्चिम बंगाल के मामले में नगरी आबादी में वर्ग स नगरी समूह/नगरों का हिस्सा क्रमशः 77.85 प्रतिशत और 81.71 प्रतिशत अधिक है। श्रेणी-स, नगरी समूह/नगर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मेघालय और तमिलनाडु राज्यों में नगरी आबादी का लगभग दो तिहाई योगदान करते हैं।

iv) महानगरीय नगरों का विकास

भारत में, कोलकाता 1901 में एक मिलियन से अधिक की आबादी वाला एकमात्र नगर था। 1911 तक मुंबई ने एक मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 1941 तक इस श्रेणी में केवल दो नगर थे, यानी, जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक थी। दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद ने 1951 तक इस श्रेणी में प्रवेश किया। अहमदाबाद और बैंगलोर ने 1961 तक, और कानपुर और पुणे ने 1971 तक। लखनऊ, नागपुर और जयपुर ने 1981 में एक मिलियन का आंकड़ा पार किया, जो कि 12 मिलियन से अधिक नगरों की संख्या को 12 तक ले आया। 1991 की जनगणना की गणना के समय 23 महानगरीय समूह/नगर थे जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक थी। दशक 1981-1991 के दौरान संख्या लगभग दोगुनी हो गई। 2001 की जनगणना के समय इसकी संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। 1981 की जनगणना के समय कुल नगरी आबादी का 25 प्रतिशत मिलियन-प्लस नगरों में केंद्रित था। वर्ष 1991 तक यह 32.54 प्रतिशत हो गया। इसका मतलब है कि 1991 में इन नगरों का देश की नगरी आबादी का लगभग एक तिहाई और देश की कुल आबादी का बारहवां हिस्सा था।

1981 में दिल्ली को छोड़कर जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का हिस्सा है, शेष 11 नगर 8 राज्यों में स्थित हैं। 1991 में, 23 महानगरीय नगर भारत के 13 राज्यों में बिखरे हुए थे। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में उनकी एकाग्रता अधिक थी, प्रत्येक में 3 ऐसे महानगरीय नगर थे। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो और 7 बिहार, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच वितरित थे। कोलकाता में 1971-81 के दशक में नगरी आबादी की सांद्रता अन्य महानगरीय नगरों की तुलना में अधिक थी। इसके बाद बैंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद थे।

1981-1991 के दौरान 23 महानगरीय नगरों ने जनसंख्या के विकास के काफी विविध स्वरूप का प्रदर्शन किया। इन महानगरीय नगरों में जनसंख्या का उच्चतम विकास विशाखापत्तनम नगरी ढेर (74.27 प्रतिशत) में दर्ज किया गया, इसके बाद हैदराबाद नगरी समूह (67.04 प्रतिशत), जोकि दोनों आंध्र प्रदेश में थे। सबसे कम वृद्धि दर कोलकाता नगरी समूह (18.73 प्रतिशत) द्वारा दर्ज की गई थी, उसके बाद पटना नगरी समूह था। कोलकाता नगरी संकुलन जिसने 1901 के बाद से ही जन्षंख्या की दृस्टि से प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया था १९९१ में यह स्थान ग्रेटर मुंबई का हो गया और कोलकत्ता दूसरे स्थान पर आ गया। इस प्रविति्त का अनुकरण करने वाले चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर रहे हैं । 1988 में, भारतीय नगरी परिदृष्य को स्पष्ट करने वाली विषमताओं का वर्णन करते हुए, राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग ने दो मुख्य पहलुओं को बतायारू (ए) जबकि भारत में नगरी केंद्र 1970 के दशक के दौरान 46.2 प्रतिशत की औसत दर से बढ़े, मिलियन-प्लस इसी अवधि के दौरान महानगरीय केंद्रों में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर केवल 29.6 प्रतिशत थी, और (इ) नगरीकरण प्रक्रिया की प्रकृति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता थी। वास्तव में, भारतीय नगरीकरण का स्थानिक स्वरूप अत्यधिक स्थानीयकृत रहा है। (इग्नू, 2017: पृष्ठ 6, 2017)

7.5.1 प्रवास

भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में, ग्रामीण लोगों का नगरी क्षेत्रों में प्रवास निरंतर रहा है और यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के नगरी आयोग ने ग्रामीण नगरी प्रवास को 'ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण महत्वश के रूप में देखा। आयोग आगे बताता है कि भूमिहीन मजदूरों, ब्राह्मणों और आदिवासियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से अधिशेष श्रम जारी करने के अलावा, ये नगर अवसर प्रदान करते हैं, जो हमारे संविधान में निहित हैं। इन लाखों लोगों के लिए, हमारे नगरी केंद्र आशा के केंद्र बने रहेंगे, जहां वे एक नया भविष्य बना सकते हैं (मेहता 1984: 778)।

भारत में, नगरी स्थानों पर प्रवास में यह वृद्धि हाल ही में हुई है जो 1930 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी। नगरी क्षेत्रों के कुल प्रवासियों में से 20 प्रतिशत व्यक्ति पाकिस्तान से, 51 प्रतिशत उसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से और 2.5 प्रतिशत अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित हैं। नगरी क्षेत्रों में आप्रवासी धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका मुख्य रूप से पुरुष चरित्र है (सरिकवल 1978: 25)।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने के कारण, अधिशेष ग्रामीण श्रम शक्ति रोजगार पाने की आशा के साथ नगरी केंद्रों में धकेल दी जाती है। अन्य कारक, जिन्होंने नगर की ओर ग्रामीण आबादी (समृद्ध वर्गों सहित) के वर्गों को खींचा है, वे विभिन्न प्रकार की आकर्शक नौकरियों, अच्छे आवास, चिकित्सा, शैक्षिक और संचार सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं।

यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिकीकरण को नगरीकरण के लिए शर्त के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब कृषि के क्षेत्र में एक रिश्तेदार उच्चतम पर बिंदु पहुंच जाता है, तो गांव से पलायन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह देश में असंतुलित भूमि / मानव अनुपात का परिणाम है।

गतिविधि 2

यदि आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो पता करें कि गाँव में आपके कितने रिश्तेदार नगरी क्षेत्रों में चले गए हैं। यह सर्वेक्षण करने के बाद, उनके प्रवास के कारण पर एक नोट लिखें।

या

यदि आप एक नगरी क्षेत्र में रहते हैं, तो एक झुग्गी पर जाएँ और उस क्षेत्र में लगभग बीस परिवारों के प्रवास के कारणों पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

7.5.2 सामाजिक-सांस्कृतिक चरित्र

नगरीकरण की प्रक्रिया ने भारत के नगरों और नगरों ने जातीयता, जाति, नस्ल, वर्ग और संस्कृति के संदर्भ में विषम चरित्र को प्राप्त किया है। नगरी क्षेत्रों में हमेशा विभिन्न संस्कृतियों का सह-अस्तित्व रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न जातीय और/या जाति समूहों ने नगर में एक दूसरे के साथ खुद को समायोजित किया है, उन्होंने अपनी पारंपरिक पहचान को बनाए रखने की भी कोशिश की है। प्रवासियों ने नगरों में विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा है। विभिन्न प्रवासी समूहों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी है। एन.के. बोस (1968: 66) बताते हैं कि प्रवासियों को ऐसे लोग परेशान करते हैं जिनके साथ उनकी भाषाई, स्थानीय, क्षेत्रीय, जातिगत और जातीय संबंध हैं। जगन्नाथन और हलधर (1989: 315) द्वारा कोलकाता (कलकत्ता) में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के एक अध्ययन से पता चलता है कि वे गाँव से जानकारी और संचार या

संचार के लिए रिश्तेदारी और जाति समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक-बहुलतावाद नगरी लोगों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम रहा है।

कई भारतीय नगरों में एक 'मिश्रित' चरित्र है, अर्थात, वे राजधानी नगर, व्यापार और वाणिज्य के केंद्र, महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन आदि हैं। इन प्रकार के नगरों में हम एक 'केंद्रीय' क्षेत्र पाते हैं, जिसमें पुराने निवासी होते हैं (श्रीनिवास 1986)। यह क्षेत्र नगर में सबसे पुराना है और इसके किनारे पर हम नए प्रवासियों को पाते हैं। इस 'केंद्रीय' आबादी के निवास का पैटर्न भाषा, जाति और धर्म के बीच एक करीबी रिश्ता दर्शाता है। बंबई को इस प्रकार के नगर के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।

लिंच (1974) यह भी बताते हैं कि कई भारतीय नगरों में, विशेष रूप से आगरा जैसे पारंपरिक नगरों में, जाति और धार्मिक समूहों के मामले में पड़ोस सजातीय बने हुए हैं। वहां जाटव विशेष क्षेत्रों में केंद्रित हैं जिन्हें मुहल्ला (वर्ल्ड) कहा जाता है। लेकिन बदलाव ज्यादातर राजनीतिकरण, शिक्षा के प्रसार और व्यावसायिक विविधीकरण के कारण हुए हैं। लेकिन डिसूजा (1974) ने देखा कि योजनाबद्ध नगर में चंडीगढ़ पड़ोस की तरह जातीयता, सामान्य हित और अन्य समानताओं के आधार पर विकसित नहीं किया गया है। इस नगर में धार्मिक गतिविधियां, मित्रता और शैक्षिक संबंध अक्सर एक ही पड़ोस में अलग-अलग होते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण ने नगरी समाज में एक नया रूप ले लिया है। यह माना जाता है कि नगरीकरण के साथ जाति नगरी क्षेत्रों में खुद को वर्ग में बदल देती है। लेकिन नगरों में जाति व्यवस्था मौजूद है, हालांकि महत्वपूर्ण संगठनात्मक मतभेद हैं। रामकृष्ण मुखर्जी प्रदर्शित करते हैं कि कोलकाता में लोग जाति-पदानुक्रम के मामले में खुद को श्रेणीबद्ध करते हैं। व्यावसायिक श्रेणियों के आधार पर स्तरीकरण भी हुआ है। उदाहरण के लिए, हेरोल्ड गॉल्ड (1965) बताते हैं कि लखनऊ के कई धार्मिक और जाति समूहों से संबंधित रिक्षावाला अपने सामान्य व्यवसाय के संबंध में बातचीत और दृष्टिकोण के पैटर्न में एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। फिर से यह पाया गया है कि नगरी क्षेत्रों में व्यवसाय के विकल्प का निर्धारण करने में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय और स्थान और स्थितिगत ध्यान (राव 1974: 275) के आधार पर जाति और वर्ग दोनों का अपना-अपना महत्व है।

विवाह और परिवार सामाजिक जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। नगरी क्षेत्रों में साथी के चयन के संबंध में जाति मानदंड लचीले रहे हैं। युवा पुरुषों और महिलाओं के मुक्त मिश्रण के अवसर बढ़ रहे हैं। स्वैच्छिक संघों ने भी अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है। परिणामस्वरूप नगरी क्षेत्रों में पहले की तुलना में अधिक अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह हुए हैं। हालांकि यह बताया गया है कि नगरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, देश के कई हिस्सों में किए गए अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि संयुक्त परिवार नगरों में कुछ जातियों जैसे कि दिल्ली के खत्रियों और मद्रास के चेट्टियारों में मौजूद हैं (विवरण के लिए देखें कपूर 1965, सिंगर 1968)।

भारत के नगरों का सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में अध्ययन किया जाना है। नगरों में प्रवासियों द्वारा कई छोटी परंपराएँ लाई गई हैं और महान परंपराओं ने भी बहु आयामी परिवर्तन प्राप्त किया है। यह तर्क दिया जाता है कि आधुनिक नगरों में महान परंपराओं के कई रूपों को संशोधित किया गया है। मिल्टन सिंगर (1968) से पता चलता है कि श्भगवान के लिए बौद्धिक और कर्मकांड के दृष्टिकोण को भक्ति दृष्टिकोण के पक्ष में खारिज

किया जा रहा है, जो मद्रास (चेन्नई) नगर में अधिक कैथोलिक और नगरी परिस्थितियों के अनुकूल है। धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोफोन, सिनेमा, ऑटोमोबाइल आदि जैसे तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया जाता है। महानगरीय नगर मद्रास (चेन्नई) में धार्मिक गतिविधियाँ घट नहीं रही हैं, बल्कि इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है "।

7.6 वर्तमान नगरीकरण से संबन्धित समस्याएं

नगरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कई समस्याओं का सामना किया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का विकास रहा है। गंदी बस्तियों की जनसंख्या भारत में सभी प्रकार के नगरों में नगरी आबादी का पर्याप्त हिस्सा है। यहां तक कि चंडीगढ़ जैसा योजनाबद्ध नगर भी मलिन बस्तियों से नहीं बचा है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में झुग्गी आबादी का प्रतिशत क्रमशः 32, 25 और 24 है। झुग्गियों में घटिया आवास, अधिक भीड़ और विद्युतीकरण, निकास , स्वच्छता, सड़कों और पीन के पानी की सुविधाओं की कमी की विशेषता है। मलिन बस्तियां बीमारियों, पर्यावरण प्रद षण, विध्वंस और कई सामाजिक तनावों का प्रजनन स्थल रही हैं। किशोर अपराधी, जुआ, जै अपराध भी झुग्गी क्षेत्रों में संख्या में बढ़े हैं। इन स्थानों पर गरीबी के संकेत सबस अधिक दिखाई देते हैं। गंदी बस्तियों का चित्रमय प्रतिनिधित्व चित्र 7.1 में दिखाया गया है।

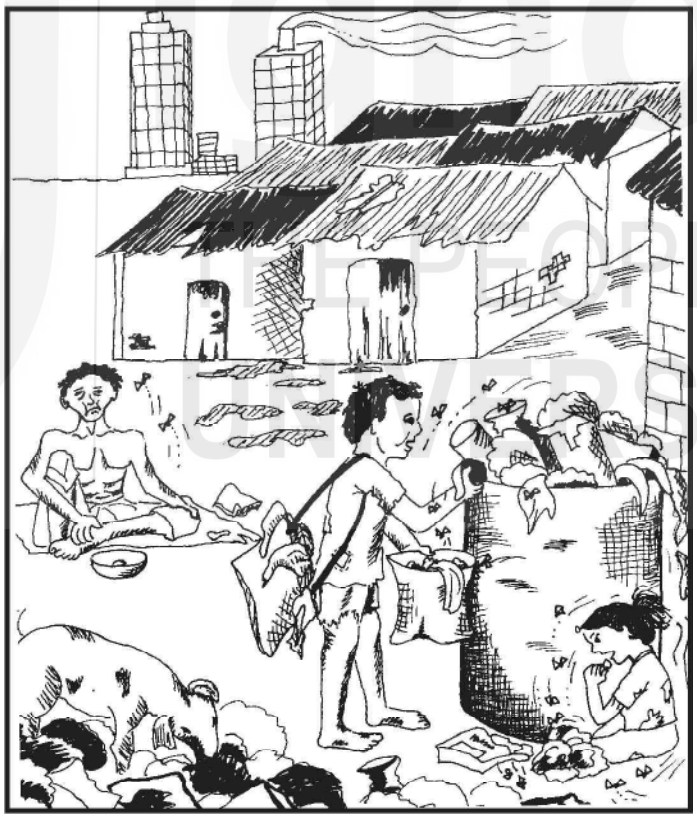

भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में आवास की कमी एक और महत्वपूर्ण समस्या रही है। दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में यह समस्या तीव्र है। आवास से संबंधित नगरी भूमि के नियोजित उपयोग पर समस्याएँ हैं। पर्याप्त आवास की कमी को विशेष रूप से निम्न आय वर्ग और नगरी गरीबों के लिए चिह्नित किया गया है। इस समस्या की गंभीरता के मद्देनजर, सरकार ने नगरी भूमि सीमा अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम आदि को पारित कर दिया है। नगरीकरण पर राष्ट्रीय परिषद ने भी सिफारिश की है कि सभी नए विकासों में से कम से कम 15 प्रतिशत का उपयोग नगरी आबादी के आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

भारत के अधिकांश नगरी केंद्रों में यातायात और परिवहन के लिए नियोजित और पर्याप्त व्यवस्था की अनुपस्थिति एक और महत्वपूर्ण समस्या है। यद्यपि हमारे महानगरों में परिवहन और उन्नत तकनीक के विभिन्न नए साधनों का उपयोग लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है, फिर भी ये वहां की बढ़ती जनसंख्या के साथ अपर्याप्त हैं। इसी प्रकार, भारत में अधिकांश नगरी केंद्रों में चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली-आपूर्ति की मात्रा अपर्याप्त है।

भारत की नगरी विकास नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि नगरी और राष्ट्रीय विकास में नगरी केंद्रों की सकारात्मक भूमिका हो, ताकि ग्रामीण-नगरी निरंतरता को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा सके। भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में आवास, स्लम निकासी, झुग्गी सुधार, भूमि अधिग्रहण और विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे।

छठी योजना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (छब्) के विकास पर विशेष जोर दिया, ताकि दिल्ली के मूल से क्षेत्रीय नगरों (राव 1983) में आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित किया जा सके। छब् की अवधारणा का उद्देश्य दिल्ली के आसपास के एक विशाल क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बेहतर क्षेत्रीय समानताएं लाना है। इसे राजधानी की वृद्धि और विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के एकीकृत विकास को शामिल करती है। 1985 में संसद के एक अधिनियमित के माध्यम से एक सांविधिक निकाय का गठन किया गया है और एक मसौदा क्षेत्रीय योजना तब से एनसीआर के विकास के लिए तैयार की गई है (भारत सरकार 1987: 597)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (छब्च्ठ) के संसाधन आधार में योजना प्रावधान के माध्यम से बजटीय आवंटन और ऋण की लाइन के रूप में उधार लेने वाले संस्थान, वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण और कर योग्य और कर-मुक्त बॉन्ड अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में शामिल हैं। एनसीआरपीबी के लिए नौवीं योजना का प्रावधान 200 करोड़ रुपये का था और नौवीं योजना के दौरान बोर्ड ने पूंजी बाजार से जुटाए जाने के लिए रु .120 करोड़ के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों की परिकल्पना की थी। छब्च्ठ ने सड़क, पुल, पानी की आपूर्ति, सीवरेज निपटान सुविधाओं आदि सहित क्षेत्र के विभिन्न नगरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की सुविधा प्रदान की है। हाल के वर्षों में सरकार ने नगरी लोगों को विशेष रूप से गरीबों को विभिन्न आवास योजनाओं के तहत मकान बनाने में मदद करने की योजना बनाई है। स्मार्ट सिटी का आइडिया भी विकसित किया गया है

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें

1) भारत में नगरी आबादी के प्रवाह में क्या रुझान है? सही उत्तर पर टिक मार्क करें।

क) एक स्थिर वृद्धि

ख) ठहराव की स्थिति

ग) उपरोक्त दोनों

घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

2) नीचे दिए गए विकल्प में से एक का चयन करके निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरें।

भारत में नगरीकरण की स्थानिक विशेषता रही है

क) स्थानीय

ख) संतुलित

ग) स्थानीय और संतुलित

घ) न तो संतुलित और न ही स्थानीयकृत

3) चार पंक्तियों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7.7 सारांश

इस इकाई में हमने गाँव, कस्बे और नगर की बुनियादी विशेषताओं पर चर्चा की है। हमने गाँव की अवधारणा पर भी विस्तार से गौर किया है और एक गाँव की प्रकृति और सामाजिक संरचना को समझाने की कोशिश की है। हमने कस्बों और नगरों को परिभाषित किया है। हमने उनकी केंद्रीय विशेषताओं पर चर्चा की। हमने आखिरकार एक नगर की वृद्धि और सामाजिक संरचना दी है। समस्याओं के साथ-साथ इसका सामना करना पड़ता है, जैसे, मलिन बस्तियों आदि में हमने नगरीकरण और सरकार की योजनाओं के परिणामों का उल्लेख किया है ताकि लोगों की समस्याओं, जैसे, बेघर, कमजोर वर्गों के लिए रोजगार आदि को हल करने में मदद मिल सके।

7.8 संदर्भ

अटल योगेश 2016. भारतीय समाज निरंतरता और परिवर्तन, पियर्सन, दिल्ली, चेन्नई ।

देसाई, ए. आर. 1961. ग्रामीण समाजशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र के लिए भारतीय समाज। बंबई।

मदन, वंदना (सम्पादन) 2002. द विलेज इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस, नई दिल्ली।

मैंडेलबाउम, डेविड जी. 1972. सोसाइटी इन इंडिया वॉल्यूम 1 कंटीन्यूइंग एंड चेंज, वॉल्यूम 2 ,निरंतरता और परिवर्तन य लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे

शर्मा के. एल. 2007. भारतीय सामाजिक संरचना और परिवर्तन, रावत प्रकाशन।

शर्मा, आर. के. 2004, अर्बन सोशियोलॉजी, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, नई दिल्ली।

सिंह, वाई 1986 भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिशर्स, जयपुर।

इग्नू 2017 (पुनर्मुद्रण), ईएसओ -12, सोसाइटी इन इंडिया, ब्लॉक 1 (च्च26-27)

सिंह, आर। 1988. भूमि, पावर एंड पीपल, सेज, दिल्ली

श्रीनिवास, एम. एन. 1972. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ओरिएंट लैंगमैन, नई दिल्ली

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

क) (ii)

ख) (iv)

ग) (iv)

घ) (iv)

ii) भारतीय गांवों में जजमानी 'प्रणाली पाई जाती है। यह संरक्षक और ग्राहकों, या जाजमान और विभिन्न जातियों के कामिन के बीच का संबंध है, जो कि आमतौर पर एक गांव के भीतर। यह जातियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान की एक प्रक्रिया है। कुछ जातियां संरक्षक हैं और कुछ ग्राहक हैं। यह एक विरासत में मिला हुआ रिश्ता है। जजमानी नियम ग्रामीण भारत में जाति पंचायतों द्वारा लागू किए जाते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

प) गाँव ने राजनीतिक व्यवस्था के उच्च स्तर से बहुत अधिक स्वायत्तता के साथ-साथ पृथकता का भी आनंद लिया। राजाओं ने दिन-प्रतिदिन के मामलों में ग्रामीणों को खुद पर शासन करने दिया। सड़कों की अनुपस्थिति और खराब संचार भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक रहे हैं ।

पप) गाँव को ष्छोटा गणतंत्रष् मानना गलत है क्योंकि राजा ने गाँव के संबंध में कई कार्य किए जैसे कि कुछ सड़कों और नहरों का निर्माण करना, ठगों और दमनकारी सैनिकों से सुरक्षा प्रदान करना और जाति क्रम के में विवादों को निपटाने के लिए अंतिम सत्ता का होना आदि । जो सत्ताधारी थे उनकेलिए ग्रामीण निष्क्रिय और असंयमी नहीं थे। वे एक बुरे राजा के खिलाफ विद्रोह करते थे और एक शासक को मदद करते थे जो उनकी जाति के थे।

अपनी प्रगति की जाँच करें 3

प) अ

पप) अ

पपप)राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा को दिल्ली की राजधानी नगर की विकास और विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली के एकीकृत विकास के लिए, इस क्षेत्र में 30,000 वर्ग मीटर है जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं।